सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

» Pg12

देश के कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21 प्रतिशतः योगी

कानपुर, शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 330, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

इनसाइड ऑपरेशन-500 का बजा बिगुल, फर्जी पत्रकारों और दलालों पर.. » Pg02

कोडीन कफ सिरप मामले में ईडी का जबर्दस्त एक्शन

ईडी का लखनऊ, वाराणसी समेत 25 ठिकानों पर छापा

मास्टरमाइंड शुभम पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से कोसों दूर, आलोक सिंह की कोठी पहुंची जांच टीम

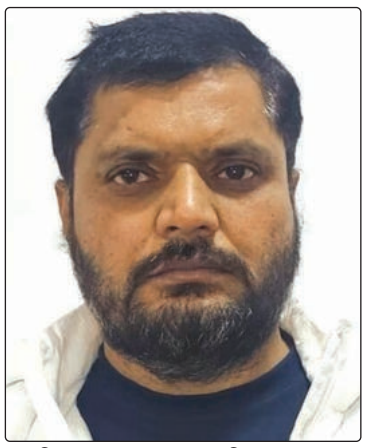

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया।

लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी और इसके अवैध कारोबार के मामले में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौकानें वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से कोसों दूर हैं। हालांकि, उसके पिता को भोला जायसवाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कार्रवाई के इसी क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी है। ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर समेत करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की है।

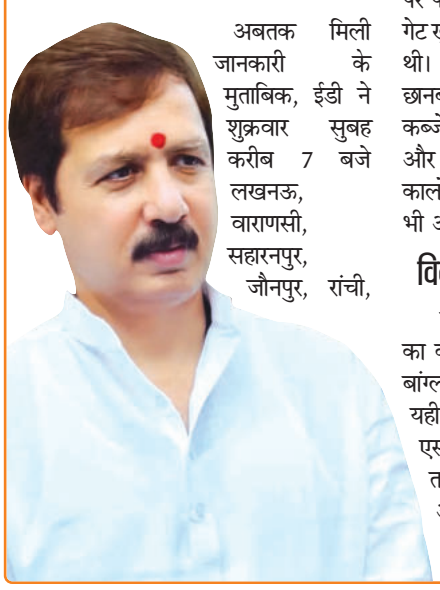

अबतक मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी ने शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद में एक साथ छापेमारी की है। इसतरह देशभर में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लखनऊ में ईडी की टीम ने आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर भी छापेमारी की है। आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है। आलोक सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी है। गुरुवार को धनंजय सिंह ने बताया कि वो आलोक सिंह को बचपन से जानते हैं।

धनंजय सिंह के बयान के दूसरे दिन ही ईडी ने आलोक सिंह समेत करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे के करीब आलोक सिंह की सुल्तानपुर रोड स्थित स्वास्तिक सिटी कोठी पर पहुंची थी। बड़ी मशक्कत के बाद घर का गेट खुला था। उसवक्त घर पर महिलाएं मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने पूरे घर में छानबीन की है। अलमारियों से कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। छापेमारी के दौरान मोबाइल और फाइल मिली है। इसके अलावा एलडीए कालोनी, ट्रांसपोर्ट नगर और सरोजनीनगर में भी अन्य ठिकानों पर छापेमारी हुई है।

विदेश तक फैला अवैध कारोबार

बताया जाता है कि नशीली कफ सिरप का कारोबार देश में ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य देशों तक फैला था। यही वजह है कि इस मामले में यूपी पुलिस, एसटीएफ, एसआईटी और ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई है। उधर आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा की 55 घंटे की रिमांड मंजूर हो गई है। 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। दोनों आरोपी लखनऊ जेल में बंद है।

मुख्य आरोपी अब तक फरार

इस मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार चल रहा है। दावा किया जा रहा है शुभम दुबई भाग गया है। हालांकि बीते दिनों पुलिस ने शुभम के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ लिया था। इस मामले में आलोक सिंह, अमित टाटा समेत करीब 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सहारनपुर में शास्त्री नगर और कपिल विहार इलाके में ईडी ने छापेमारी की है। एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक विभोर राणा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। विभोर और उसका भाई विशाल भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

धनंजय सिंह ने अखिलेश को घेरा, बोले- सबूत दें, माफी मांगे

कफ सिरप प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। धनंजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव बिना सबूत उनके नाम को घसीट रहे हैं और उन्हें इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख तथ्यहीन बयानबाजी कर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर अखिलेश दावा कर रहे हैं कि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है, तो सबूत पेश करें। वरना यह देश को गुमराह करना है। मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा।

उत्तराखंड में 65 फर्जी फर्में बनाकर तस्करी, अभिषेक ने उगले होश उड़ाने वाले राज

फेंसेडिल कफ सिरप बनाने वाली एबॉट फॉर्मास्युटिकल कंपनी की बांग्लादेश तस्करी करने वाले सिंडिकेट के साथ मिलीभगत के पुख्ता प्रमाण एसटीएफ के साथ लगे हैं। यूपी एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार सहारनपुर के अभिषेक शर्मा ने बताया कि विभोर राणा और विशाल सिंह की जीआर ट्रेडिंग फर्म बंद होने के बाद एबॉट के अधिकारियों से मिलीभगत कर विशाल की फर्म बीएन फार्मास्युटिकल को केयरिंग एंड फारवर्डिंग एजेंट (सीएफए) बनाकर कारोबार किया गया।

अभिषेक ने कबूला कि सचिन मेडिकोज के नाम से उसकी फर्म का नाम बदलकर मारुति मेडिकोज कर दिया। सीए अरुण सिंघल ने विशाल और विभोर के कहने पर मेरे भाई शुभम शर्मा समेत कई लोगों के नाम से फर्जी फर्में बनाई थी। मारुति मेडिकोज को जनवरी 2024 में एबॉट ने उत्तराखंड का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। उसने बताया कि मेरे नाम पर भी दिल्ली में एक फर्म एवी फार्मास्यूटिकल्स पप्पन यादव के साथ साझेदारी में बनवा दी। इसका काम विशाल सिंह और विभोर राणा के साथी सौरभ त्यागी और पप्पन यादव देखते थे। मारुति मेडिकोज में सिरप मंगाने के बाद उत्तराखंड में बनी 65 फर्जी फर्मों के कागजों पर बिक्री दिखाते थे।

कफ सिरप मामले में सीएम योगी सख्त

60 दिन में 52 जिलों की 332 फर्मों पर छापेमारी, 133 फर्मों की एफआईआर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का सीधा असर अब प्रदेश में अवैध नशे के कारोबार पर दिखाई दे रहा है। कोडिनयुक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स कैटेगरी की दवाओं की तस्करी और अवैध डायवर्जन रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने पिछले दो महीनों में देश का अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन चलाया है। सीएम योगी के निर्देश पर एफएसडीए की ओर से शुरू की गई इस कार्रवाई ने न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में नई नजीर पेश की है।

दो महीने पहले सीएम योगी के सख्त निर्देश पर एफएसडीए ने प्रदेश के 52 जिलों में एकसाथ औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की गहन जांच शुरू की थी। इसमें 332 फर्मों की जांच की गई थी। जिनमें से 133 फर्में अवैध व्यापार और नशे के रूप में दवाओं के डायवर्जन में शामिल पाई गई थी। इनमें से कई फर्में सिर्फ कागजों पर ही मौजूद थी। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा संचालकों को जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल कार्रवाई जारी है।

इस संबंध में एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि सीएम योगी के साफ निर्देश थे कि कार्रवाई केवल लाइसेंस रद्द करने तक सीमित न रहे। इसी के तहत पहली बार कोडिनयुक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स दवाओं के अवैध डायवर्जन में शामिल लोगों पर एनडीपीएस और बीएनएस की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए है। जिससे कार्रवाई और कठोर हो गई है।

साथ ही सभी डीएम को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की संस्तुति भेजी गई है। जांच में पता चला कि यूपी के कई जिलों से कोडिनयुक्त कफ सिरप की बड़ी खेप नेपाल और बांग्लादेश में नशे के रूप में भेजी जा रही थी। इनमें लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गाजियाबाद और वाराणसी मुख्य हॉटस्पॉट रहे थे।

कफ सिरप तस्करी के मामले वाराणसी, जौनपुर, कानपुर नगर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, रायबरेली और संतकबीर नगर जिले से सामने आया है। साथ ही हरदोई, भदोही, अमेठी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, बस्ती, अंबेडकनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, मीरजापुर, बांदा और कौशांबी से भी तस्करी के मामले सामने आए हैं।

ऑपरेशन-500 का बजा बिगुल, फर्जी पत्रकारों और दलालों पर कसेगा शिकंजा

» कमिश्नरेट पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, 500 घंटे चलेगा अभियान

» झूठी शिकायत पर भी होगी कार्रवाई, आरोपियों में मचा हड़कंप

» प्रमुख संवाददाता/ स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने गुरुवार से ऑपरेशन-500 की शुरुआत कर दी है। इसका लक्ष्य वसूलीबाज यूट्यूबर, कथित पत्रकार, थानों के दलाल और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करना है। कमिश्नरेट की ओर से शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर-7839863274 जारी किया गया है। इस नंबर पर भेजी गई शिकायतें पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। पुलिस कमिश्नर

रघुवीर लाल ने बताया कि लंबे समय से उगाही, रंगदारी, दलाली और जांच के नाम पर आम लोगों को परेशान किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं।

ऐसे में 500 घंटे का यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। शिकायत करने वाला चाहे तो व्हाट्सएप पर साक्ष्य भेज सकता है या कार्यालय समय में सीधे अफसरों से मिलकर भी अपनी बात रख सकता है।पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि गलत सूचना देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की गई है कि वे सटीक सूचना देकर शहर के माहौल को स्वच्छ बनाने में योगदान दें।

किन मामलों में भेज सकते हैं सूचना

थानों में दलाली और अवैध वसूली से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है, जिसमें वे लोग शामिल हैं जो पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पैसे लेकर मामलों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही किसी भी क्षेत्र में हो रही आपराधिक गतिविधियों, सक्रिय अपराधियों या उनकी संदिग्ध हलचलों की सूचना भी कमिश्नरेट पुलिस को भेजी जा सकती है।शहर में सक्रिय फर्जी यूट्यूबर्स या कथित पत्रकार जो ब्लैकमेलिंग और उगाही में संलिप्त हैं, उनके बारे में भी तथ्यात्मक जानकारी साझा की जा सकती है। इसी प्रकार ऐसे पुलिसकर्मी जिन पर आपराधिक प्रवृत्ति, दबाव बनाकर वसूली या अनैतिक कार्यों में शामिल होने के आरोप हों,

उनके खिलाफ भी प्रमाण सहित शिकायत भेजने की अपील की गई है।नकली दवाओं, मिलावटी खाद्य पदार्थों, अवैध शराब के उत्पादन एवं बिक्री, तथा नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ी किसी भी सूचना को भी गंभीरता से लिया जाएगा। चोरी या लूट के माल को खरीदने-बेचने वाले नेटवर्क से जुड़ी जानकारी भी इस अभियान के तहत अत्यंत उपयोगी मानी जाएगी।किसी क्षेत्र में चल रहे जुआ या सट्टेबाज़ी के रैकेट की जानकारी भी साझा की जा सकती है, जबकि किसी गांव या मोहल्ले में अचानक आकर रहने वाले संदिग्ध व्यक्ति के व्यवहार या गतिविधियों की रिपोर्ट करना भी जरूरी माना गया है। इसके अलावा अवैध तरीके से हथियार बनाने, रखने या बेचने वाले तत्वों के बारे में मिलने वाली सूचना पर भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

हाईवे पर चलती कार में महिला के हाथ में तमंचा, वीडियो वायरल

कार सवार युवती और युवक ने उड़ाई कानून-व्यवस्था की धज्जियाँ

» प्रमुख संवाददाता/ स्वराज इंडिया

कानपुर। हाईवे पर चलती कार के अंदर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में कार सवार एक महिला ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में बैठी दिखाई दे रही है, जबकि गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रही है।

इस दौरान महिला तमंचा निकालकर उसकी नाल अपनी कनपटी पर टिका लेती है। इसके तुरंत बाद पीछे बैठा युवक भी तमंचे की ओर हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। कुछ ही सेकेंड बाद कार चला रहा युवक महिला के हाथ से तमंचा लेता है और चलती कार की खिड़की से खुले हाईवे पर गोली चला देता है।

यह वीडियो बर्रा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि हाईवे पर चलती कार में तमंचे के साथ की गई यह लापरवाही बेहद गंभीर मामला है।

वीडियो में दिख रही युवती की पहचान बर्रा निवासी मनीषा अरोड़ा के रूप में की जा रही है। मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

चलती ट्रेन से गिरा युवक, हैलेट अस्पताल में हालत गंभीर

» ट्रेन संख्या 54156 से गिरा था युवक, अभी तक नहीं हो सकी पहचान

» प्रमुख संवाददाता/ स्वराज इंडिया

कानपुर। बिल्हौर के निकट एक अज्ञात व्यक्ति चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना करीब 1ः16 बजे हुई और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक ट्रेन संख्या 54156 से गिरा था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पीआरवी 3203 को दी, जिसके बाद पुलिस और राहत दल वहीं पहुंच गए।घायल को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर

लिया है। चिकित्सा टीम के अनुसार युवक की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि घायल व्यक्ति की पहचान की जा रही है और उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि युवक कैसे और किन परिस्थितियों में ट्रेन से गिरा।

सेंट्रल स्टेशन व गोविंदपुरी होकर जाएगी एक-एक ट्रेन

कानपुर। यात्री लोड घटाने के लिए रेलवे ने अलीपुर द्वार-दिल्ली वनवे विशेष ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 13 दिसंबर को एक फेरा चक्कर लगाएगी। इसमें 18 कोच होंगे। यह कानपुर सेंट्रल स्टेशन से होकर गुजरेगी। उत्तर-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन नंबर- 05483 अलीपुर द्वार जंक्शन (पश्चिम बंगाल) से शनिवार को रात 11:10 बजे रवाना होगी। 14 दिसंबर को दोपहर 12ः50 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।

ट्रेन नंबर- 04103 प्रयागराज-लालगढ़ विशेष ट्रेन एक फेरा में 12 दिसंबर शुक्रवार को चलेगी। शशिकांत ने बताया कि यह ट्रेन प्रयागराज से शुक्रवार को रात आठ बजे रवाना होगी और फतेहपुर होते हुए रात 10:45 बजे गोविंदपुरी स्टेशन आएगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद रवाना होकर विभिन्न स्टेशन होते हुए अगले दिन शनिवार रात 08:40 बजे लालगढ़ (राजस्थान) पहुंचेगी।

केआईटी कॉलेज में परीक्षा केंद्र बदलने पर तीसरे दिन भी विरोध जारी

»प्रमुख संवाददाता / स्वराज इंडिया

कानपुर। महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) कॉलेज में शुक्रवार को भी छात्रों का विरोध जारी रहा। एमबीए, बीटेक और बीसीए के छात्र-छात्राओं ने परीक्षा केंद्र में अचानक किए गए बदलाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन गुरुवार से लगातार दूसरे दिन जारी रहा है, जबकि छात्रों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा।छात्रों का कहना है कि पूरे सत्र में उन्हें आश्वस्त किया गया था कि परीक्षाएं केआईटी कॉलेज परिसर में ही होंगी, लेकिन अब जब परीक्षाओं में मात्र दस दिन बचे हैं, तब अचानक उन्हें बताया गया कि परीक्षाएं विश्वविद्यालय में आयोजित होंगी।

» अचानक परीक्षा केंद्र बदले जाने से भड़के छात्र, बोले-दस दिन में नई जगह पर परीक्षा देना मुश्किल

छात्रों का आरोप है कि यह निर्णय जल्दबाजी और बिना पूर्व सूचना के लिया गया है, जिससे विशेष रूप से दूर-दराज से आने वाले छात्रों को भारी दिक्कत होगी।बीटेक प्रथम वर्ष और बीसीए प्रथम वर्ष के छात्र अभय राठौर ने बताया कि नए परीक्षा केंद्र तक पहुंचना कई छात्रों के लिए चुनौती है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि कॉलेज प्रबंधन निर्णय वापस नहीं लेता, तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। कई छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें निलंबन और परिजनों को शिकायत की धमकी दी जा रही है।घटना की जानकारी मिलते ही महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंचे और छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करके समाधान निकालने की कोशिश की।वहीं कॉलेज के डायरेक्टर बृजेश वात्सनेय ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा जून 2024 में जारी निर्देशों के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन छात्रों को समझाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर थानाध्यक्ष महाराजपुर ने कहाकि पहले कॉलेज प्रशासन स्वयं परीक्षा कराने की बात कर रहा था परंतु बाद में परीक्षा की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी को सौंप दी गई जिस वजह से छात्रों में भारी आक्रोश है और वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बाकी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शांति व्यवस्था पर कायम रखने पर ध्यान दिया जा रहा है।

आरोग्य योजनाएँ शुरू, पर बीमितों तक खबर भी नहीं

» सेवा सुधार की घोषणाएँ सिर्फ कागज़ों और कार्यक्रम के सभागार तक , बीमित कर्मचारी लाभ से अनभिज्ञ

»इलाज की स्वतंत्रता, दवा उपलब्धता और लाभों की जानकारी अब भी उनके पास नहीं

»प्रमुख संवाददाता / स्वराज इंडिया

कानपुर। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आयोजित आरोग्य मंथन-2025 कार्यक्रम को बीमित कर्मचारियों के हित में बताया गया, परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत सामने आई है। जिन कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, उन्हें इसकी कोई सूचना ही नहीं दी गई।

न विभाग की ओर से संदेश भेजा गया, न फोन पर कोई सूचना मिली और न ही औषधालयों एवं बीमा अस्पतालों में इस संबंध में कोई सूचना-पट्ट लगाया गया। विशेष बात यह है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 13 नवम्बर 2023 को जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि बीमित व्यक्ति देश के किसी भी औषधालय या बीमा अस्पताल से उपचार और दवा प्राप्त कर सकता है, पर यह महत्वपूर्ण सुविधा और अधिकार आज भी अधिकांश कर्मचारियों को ज्ञात नहीं है।

कई स्थानों पर अब भी बीमित कर्मचारियों को पहले अपनी मूल डिस्पेंसरी जाओ जैसी पुरानी व्यवस्था में उलझाया जा रहा है। बीमित कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं निःशुल्क उपचार, दवाएँ, मातृत्व सुविधा, बीमारी भत्ता, आश्रित लाभ, दीर्घकालीन रोगों की 90 दिन की दवा के बारे में जागरूक करना नियोक्ता, श्रम विभाग और बीमा निगम तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। किन्तु जागरूकता का कोई व्यवस्था तंत्र न होने के कारण कर्मचारी न अपने अधिकार जान पाते हैं और न योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से उठा पाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक विभाग सूचना प्रसार की जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेता तथा कार्यक्रमों की सूचना सीधे बीमित कर्मचारियों तक नहीं पहुँचाई जाती,

तब तक इस प्रकार के आयोजन केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। सूचना की कमी और व्यवस्थागत ढिलाई के कारण करोड़ों रुपये की योजनाएँ भी अपने असली उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही हैं।

रजिस्ट्री ऑफिस शिफ्टिंग पर आर-पार के मूड में अधिवक्ता

आज से कलम बंद हड़ताल शुरू, बार एसोसिएशन एवं लॉयर्स एसोसिएशन ने संयुक्त बैठक में लिया फैसला, दस्तावेज़ लेखक, टाइपिस्ट और स्टाम्प वेंडर भी दे रहे साथ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील से करीब दो किलोमीटर दूर सुभानपुर गांव में रजिस्ट्री कार्यालय शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव ने अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। फैसले को मनमाना और अव्यवहारिक बताते हुए बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन ने गुरुवार को संयुक्त बैठक कर कलम बंद हड़ताल का ऐलान कर दिया। सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं, बल्कि दस्तावेज़ लेखक, टाइपिस्ट और स्टाम्प वेंडर भी आंदोलन में कूद पड़े हैं, जिससे रजिस्ट्री से जुड़े सभी कार्य ठप हो गए। आंदोलन के व्यापक और अडिग होने का संदेश साफ है वकील समुदाय अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील परिसर से दूर किसी गांव में रजिस्ट्री दफ्तर शिफ्ट करना हजारों लोगों को परेशान करने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय बिना किसी धरातली आधार और स्थानीय जरूरतों को समझे लिया गया है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी अगर रजिस्ट्री कार्यालय को सुभानपुर भेजने की जिद नहीं छोड़ी गई, तो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो तहसील के दरवाजे भी बंद कर देंगे। यह लड़ाई अब हर स्तर पर लड़ी जाएगी। बार एवं लॉयर्स ने प्रशासन और उच्चाधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप कर प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है।

महीनों से की जा रही थी जमीन की तलाश

नए रजिस्ट्रार कार्यालय के निर्माण के लिए महीनों से भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही थी। अधिकारियों ने कई गांवों का निरीक्षण किया, लेकिन अंत में सुभानपुर मुरादनगर की जमीन को उपयुक्त मानकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। जैसे ही अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने इसे मनमाना निर्णय बताते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया।

रजिस्ट्री से जुड़े कामकाज पर पड़ेगा असर

कलमबंद हड़ताल के चलते आज से भूमि रजिस्ट्री से संबंधित सभी कार्य प्रभावित रहेंगे। आम जनता को रजिस्ट्री कराने, नवीनीकरण, नामांतरण और सत्यापन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि लाखों रूपये के राजस्व का भी नुकसान होगा।

जिस स्थान पर वर्तमान में उप निबंधन कार्यालय स्थित है, वहाँ आसपास पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। ऐसे में कार्यालय को तहसील से दूर भेजने का निर्णय पूरी तरह अव्यवहारिक और असुरक्षित है। ग्रामीण इलाके में बनने जा रहे नए उप-निबंधक कार्यालय में न तो पर्याप्त सुरक्षा है और न ही नागरिकों के लिए सुविधाजनक पहुँच। यह फैसला असंवेदनशील अधिकारियों की जिद का परिणाम लगता है। मैं इस मुद्दे को गंभीरता से उठाऊंगा। माननीय सांसद जी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कराकर समस्या का स्थायी समाधान कराया जाएगा। प्रशासन मनमानी बंद करे और जनता तथा अधिवक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता दे।

-अधिवक्ता जे.पी. कटियार
पूर्व उपाध्यक्ष, भाजपा

उप-निबंधक कार्यालय को तहसील से हटाकर बाहर ले जाने का फैसला, न्यायिक व्यवस्था को बिखेरने जैसा है। वकील सिर्फ बहस नहीं करते, व्यवस्था को चलाए रखने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हम रोज़ हजारों लोगों को सुविधाएँ और सुरक्षा देते हैं। मैंने अपनी पूरी उम्र इस तहसील में गुज़ारी है। यहाँ की चुनौतियाँ, यहाँ की ज़रूरतें, हम बेहतर जानते हैं। हमारा साफ कहना है। तहसील से उप-निबंधक कार्यालय हटने नहीं दिया जाएगा।

अनिल पाण्डेय, वरिष्ठ अधिवक्ता

बिल्हौर बार एसोसिएशन और द लॉयर्स एसोसिएशन की आम बैठक में सर्वसम्मति से यह तय कर दिया गया है कि कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। तहसील परिसर में जो उप-निबंधक कार्यालय चल रहा है, उसे दो किलोमीटर दूर ठेल देने का फैसला किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। ऊपर से तीन किलोमीटर दूर ग्राम न्यायालय की स्थापना। यह आखिर किसकी समझदारी है? क्या वकील इधर से उधर तक चकरघिन्नी की तरह नाचता फिरता रहेगा? हम अधिवक्ता हर स्तर पर आंदोलन करने को पूरी तरह तैयार हैं।

- सौरभ कटियार, महामंत्री, बिल्हौर बार एसोसिएशन

शासन और प्रशासन समय-समय पर अधिवक्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसे फैसले लेती रही है, लेकिन इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तहसील के भीतर चल रहा उप-निबंधक कार्यालय हमारी जरूरत है, किसी का प्रयोगशाला नहीं। हम इसे तहसील से हटाकर दूसरी जगह बनने नहीं देंगे। अधिवक्ताओं को कमजोर समझने की भूल प्रशासन बार-बार करता है।और बार-बार उसे ही गलत साबित होना पड़ेगा।

विनय कुमार गौतम, अधिवक्ता

रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि यहाँ जगह नहीं है यह सिर्फ बहाना है, नीयत में खोट है। वकील और जनता तो वर्षों से यहीं काम कर रहे हैं, दिक्कत अगर है तो व्यवस्था सुधारने वालों को होनी चाहिए। जगह बहुत है। कुर्सी कम पड़े तो कुर्सी बढ़ाई जाती है, दफ्तर नहीं भगाया जाता। दफ्तर को तहसील से बाहर ले जाना जनता पर सजा थोपना है, और इस सजा को वकील किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे।

- राजीव कटियार
महामंत्री द लॉयर्स एसोसिएशन बिल्हौर

बार एवं लायर्स के हर अधिवक्ता ने कलम रख दी है, और यह सिर्फ हड़ताल नहीं हमारी चेतावनी है। रजिस्ट्रार कार्यालय ले जाने का फैसला जनता के साथ खिलवाड़ है। जब रजिस्ट्री के लिए लोग रुपए, कागज़ और परिवार की उम्मीद लेकर तहसील पहुंचते हैं, तो उन्हें सुनसान गांव भेजना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह निर्णय वापस लो। प्रशासन गलती कर चुका है, अब उसे सुधारना भी उसी की जिम्मेदारी है।

- अजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन बिल्हौर

रजिस्ट्री कार्यालय को तहसील के पास ही इसलिए रखा जाता है ताकि बैंक, स्टाम्प, वेरिफिकेशन और सुरक्षा व्यवस्था एक-दूसरे के साथ समन्वय में रहें। सुभानपुर गांव में कार्यालय स्थापित करना इस पूरी व्यवस्था को तोड़ देना है। यह सिर्फ दूरी की समस्या नहीं, बल्कि सिस्टम की रीढ़ तोड़ने वाला निर्णय है।प्रशासन को लगता है कि वकील चुप बैठे रहेंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। रजिस्ट्री कार्यालय किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे।

- महेंद्र त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता

अगर यही चलना है तो कल को तहसील भी खेत में बना दीजिए। दूरदराज गांव में रजिस्ट्री कार्यालय भेजना जनता को परेशान करने की साफ नीयत दिखती है। बार इसका खुला विरोध करती है और इस निर्णय को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी।

- महेंद्र सिंह कुशवाहाए पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन बिल्हौर

तहसील के पास की सुविधाएं छोड़कर दफ्तर को गांव में धकेलना किसकी बुद्धिमानी है? वहां न पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, न सुरक्षा और न ही पहुंच। जिस रजिस्ट्री में रिश्ता, जमीन और बड़ी धनराशि दांव पर होती है, उसे सुनसान जगह पर ले जाना जनता की दुर्गति करना है।

- अमित तिवारी, अधिवक्ता

यह एकतरफा और अव्यवहारिक फैसला है। हम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि गांव में रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अधिवक्ता एक साथ पूरी ताक़त से विरोध करेंगे। और किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। फिर जीत होकर रहेगी।

- अमित श्रीवास्तव, पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन बिल्हौर

सम्पादकीय

सोशल मीडिया प्रतिबंध की आस्ट्रेलियाई पहल

पश्चिमी देश, जिस सोशल मीडिया के गुणगान करते नहीं अघाते थे, अब उन्हें इससे बच्चों में पनपती विकृतियों की हकीकत समझ में आने लगी है। सुगबुगाहट तो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक प्रतिबंधों को लेकर हो रही है, लेकिन इस दिशा में पहल करने का साहस आस्ट्रेलिया ने सुधारवादियों के दबाव में उठाया है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार इसलिए वापस ले रहे हैं ताकि बच्चों के बच्चे होने के अधिकार और माता-पिता की मानसिक शांति के अधिकार की रक्षा हो सके। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि यह सुधार जिंदगियां बदल देगा। साथ ही आस्ट्रेलिया के बच्चों को बचपन जीने का मौका देगा। आज दुनिया के तमाम देश मंथन कर रहे हैं यदि आस्ट्रेलिया यह पहल कर सकता है तो वे क्यों नहीं कर सकते।

इनमें वे तमाम अभिभावक भी शामिल हैं जो अपने बच्चों की आत्महत्या के लिये सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं। उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलिया में यदि सोशल मीडिया मंच 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट हटाने में असफल रहते हैं, तो उन्हें करीबन पांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना चुकाने के लिये बाध्य होना पड़ सकता है। आस्ट्रेलियाई सरकार क्रिसमस तक मूल्यांकन करेगी कि ये प्रतिबंध कितने कारगर साबित हुए हैं।

निस्संदेह, आस्ट्रेलिया की पहल ने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखने की मुहिम को नई ऊर्जा दे दी है। कमोवेश, भारत जैसे देश भी सोशल मीडिया की असामाजिकता का दंश झेल रहे हैं। इसमें बच्चों के साथ ऑनलाइन बुलिंग से लेकर ऑनलाइन ठगी तक के तमाम मामले गाहे-बगाहे सामने आते रहते हैं। विडंबना है कि आज सोशल मीडिया पर प्रसारित वयस्कों की सामग्री से बच्चे जाने-अनजाने में परिचित हो रहे हैं। वे समय से पहले वयस्क हो रहे हैं। जिससे समाज में तमाम तरह की सामाजिक विकृतियां पैदा हो रही हैं। निस्संदेह, इससे आने वाले समय में घातक सामाजिक विद्रूपताएं पैदा हो सकती हैं। दरअसल, बच्चों के लगातार घंटों कथित सोशल मीडिया में सक्रिय रहने से उनमें तमाम शारीरिक व मानसिक विसंगतियां पैदा हो रही हैं। उन्हें संस्कार अब माता-पिता व शिक्षक नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दोहन करने वाले निहित स्वार्थी तत्व दे रहे हैं। जो कि भारतीय जीवन-मूल्यों व संस्कारों से मेल नहीं खाते। आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इतनी अश्लील व द्विअर्थी सामग्री का प्रवाह है कि हमारे किशोर आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। सोशल मीडिया के घातक प्रभाव के चलते आज बच्चों के नायक बदल गए हैं।

उनके आदर्श बदल गए हैं। उनका नजरिया बदल रहा है। सोशल मीडिया के कतिपय मंचों पर अश्लील सामग्री की उपलब्धता ने किशोरों में ब्रह्मचर्य के भारतीय मूल्यों को ताक पर रख दिया है। विडंबना यह है कि घंटों सोशल मीडिया पर बैठे रहने वाले बच्चे शारीरिक सक्रियता से दूर हो रहे हैं। जिससे उनमें मोटापा व अनेक गैर संक्रामक रोग पनप रहे हैं। वे किशोर अवस्था में मधुमेह आदि उन रोगों के शिकार बन रहे हैं जो कभी बड़ी उम्र के लोगों को हुआ करते थे।

एकता का वाहक बने स्वतंत्रता का अस्त्र

विश्वनाथ सचदेव

देश का हर नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, भारतीय है, भारत-माता का अंश है। 'वंदे मातरम?' गीत के एक हिस्से को ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारना बहस का विषय नहीं है। बहस इस बात...देश का हर नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, भारतीय है, भारत-माता का अंश है। 'वंदे मातरम?' गीत के एक हिस्से को ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारना बहस का विषय नहीं है। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि कैसे 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता को बनाये रखा जाये। 'बेकार की बहस मत करो' यह पांच शब्द शायद ही किसी ने न सुनें या न बोले होंगे। इस बहस का सीधा-सा मतलब किसी विवादास्पद विषय पर विचार-विमर्श करके एक स्वीकार्य नतीजे पर पहुंचना होता है।

हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में संसद अथवा विधानसभाओं में जब बहस की जाती है तो इसके मूल में कोई ऐसा विषय होता है जो विवादास्पद हो, जिस पर विचार करने वालों में विवाद हो। तब विषय पर संवाद करके किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। लेकिन, जब विवाद की स्थिति ही न हो, किसी विषय पर मतभेद हो ही नहीं तो फिर बहस क्यों? उस दिन जब संसद में हमारे 'राष्ट्रीय गीत' को लेकर बहस हो रही थी तो एक सवाल बार-बार मन में उठ रहा था यह बहस हो क्यों रही है? 'वंदे मातरम?' हमारी आज़ादी की लड़ाई का महामंत्र था, हमारे पूर्वजों ने इस मंत्र को हथियार बनाकर यह लड़ाई जीती थी। फिर जब संविधान-सभा में राष्ट्रगान को लेकर विचार हो रहा था तो सदस्यों ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना 'जन-गण-मन' को 'राष्ट्रगान' के रूप में स्वीकारा और बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना 'वंदे मातरम?' के प्रारंभिक अंश को 'राष्ट्रगीत' की मान्यता दी गयी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी यह राष्ट्रगीत गाया जाता था और बाद में भी इसे राष्ट्रगान के समकक्ष ही सम्मान दिया गया। आज़ादी की लड़ाई का साझा मंच थी कांग्रेस। कांग्रेस के हर अधिवेशन में तब भी, और अब भी, इसे पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है। फिर 'बहस' किस बात की है?आज से डेढ़ सौ साल पहले, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने उपन्यास 'आनंदमठ' में भी जोड़ा। देखते ही देखते यह 'वंदे मातरम?' हमारी आज़ादी की लड़ाई का महामंत्र बन गया। इस मंत्र की शक्ति और लोकप्रियता ने अंग्रेज़ों को दहला दिया था। उन्होंने इस 'जयघोष' पर ही प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध ने इसे और ताकतवर बनाया।

कोड़े बरसते रहे, वंदे मातरम? का जयघोष गूंजता रहा। । महत्वपूर्ण है यह जानना कि 'जन गण मन' को राष्ट्रगान और 'वंदे मातरम?' को राष्ट्रगीत घोषित करके इस बारे में भ्रम के इस अध्याय को समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए वंदे मातरम? की महान रचना का 150वां साल मनाना तो समझ में आता है, पर इस पर 'बहस' किस बात की इस 'बहस' की मांग सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से की गयी थी। होना तो यह चाहिए था कि इस अवसर का उपयोग उन स्वतंत्रता- सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन के लिए किया जाता; यह संकल्प लिया जाता कि हम उन सेनानियों के बलिदान को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे; उनके सपनों को साकार करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। पर हुआ यह कि संसद में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सांसदों ने इसे राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर बना दिया! यह अवसर मिल-जुल कर उत्सव मनाने का था, दुर्भाग्य ही है कि हमारे नेताओं ने इसे एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने तक ही सीमित करके रख दिया।

अवसर था कि हमारे नेता इस राष्ट्रगीत की महत्ता समझाते, यह बताते कि कैसे इस गीत के दो शब्दों 'वंदे मातरम?' ने देश में आज़ादी की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ला पहुंचाया था।

काम और जीवन के बीच संतुलन जरूरी

सेहत से उत्पादकता वृद्धि

डा. सुधीर कुमार

हम अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण वापस लें और काम को उसके तय दायरे में ही रखें। यह एक संदेश है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं, और हमें अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय चाहिए।

हमें रिचार्ज होने के लिए 'ऑफ बटन' दबाने की जरूरत है।लोकसभा में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' बिल पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद कार्यालय से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देना है। यह बिल अभी संसद में सिर्फ 'प्राइवेट मेंबर बिल' के तौर पर पेश हुआ है, जिसका कानून बनना थोड़ा मुश्किल होता है। पर इसने एक ज़रूरी बहस तो छेड़ दी है।

सीधे शब्दों में, यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि आपकी निजी ज़िंदगी और काम की ज़िंदगी के बीच एक साफ़ सीमा खींची जा सके। यह बिल कर्मचारियों को यह कानूनी अधिकार देता है कि वे काम के घंटों के बाद अपने बॉस या सहकर्मियों के फ़ोन कॉल, ईमेल या मैसेज को नज़रअंदाज़ कर सकें, जिससे उनके निजी जीवन और आराम के समय का सम्मान हो सके। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई एंटिटी (कंपनी या सोसाइटी) नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर कर्मचारियों की कुल सैलरी का 1 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। यह बिल नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लोगों को तनाव और बर्नआउट से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि लगातार 'ऑन-कॉल' रहने की स्थिति में दिमाग को सही से आराम नहीं मिल पाता। इस बिल का सबसे बड़ा लाभ

यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अलावा, यह कानून लोगों को उनका निजी समय वापस दिलाता है, जिससे वे परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। निजी और पेशेवर जीवन के बीच यह संतुलन बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह नींद की कमी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकता है, और उत्पादकता में सुधार करता है। निस्संदेह, आराम और तरोताज़ा महसूस करने वाले कर्मचारी अगले दिन अधिक लगन और बेहतर ढंग से काम करते हैं, जो यह साबित करता है कि आराम करने से उत्पादकता बढ़ती है, कम नहीं होती।

इस बिल में दो अद्वितीय और मज़ेदार सुझाव भी दिए गए हैं।

पहला, यह बिल देश भर में 'डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स' बनाने का प्रस्ताव करता है। इन सेंटरों का मकसद एक ऐसी जगह प्रदान करना होगा जहां कर्मचारी स्वेच्छा से जाकर डिजिटल उपकरणों से दूर रह सकें और व्यक्तिगत बातचीत तथा आराम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। दूसरा, बिल यह सुझाव देता है कि कर्मचारियों को काउंसलिंग सर्विस प्रदान की जाए।

इस काउंसलिंग का लक्ष्य उन्हें यह सिखाना होगा कि व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में डिजिटल साधनों का उपयोग कब और कैसे विवेकपूर्ण तरीके से करना है, जिससे वे अपने काम और निजी समय के बीच एक स्पष्ट संतुलन स्थापित कर सकें। यानी, आपको सिखाया जाएगा कि इंस्टाग्राम पर रील देखना और बॉस का ईमेल चेक करना, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं।यह एक वैश्विक रुझान है, जहां दुनिया के कई विकसित देश अपने कर्मचारियों के 'काम से वियोग का अधिकार' को कानूनी रूप से लागू कर रहे हैं। भारत अकेला नहीं है; फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल जैसे कई प्रमुख राष्ट्रों ने यह पहचान लिया है कि एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने और कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 'काम से वियोग का अधिकार' आवश्यक है।

फ्रांस इस अधिकार को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। उसने 2017 में ही कानून बनाकर बड़ी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे सुनिश्चित करें कि कर्मचारी काम के घंटों के बाद डिजिटल संचार से पूरी तरह से वियोग कर सकें।

शातिरों का शातिर निकला ठग रवींद्र नाथ सोनी, लगातार खुल रहे बड़े राज

» एसआईटी ने देहरादून-मसूरी में लगाई दौड़, पॉश कॉलोनियों से लेकर होटलों तक खंगाले ठिकाने

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। कई देशों में 1500 करोड़ की ठगी करने वाले महाठग रवींद्र नाथ सोनी की जांच नई दिशा में बढ़ गई है। कानपुर एसआईटी उसे लेकर गुरुवार को देहरादून पहुंची, जहां उसे पहले गिरफ्तार कर कानपुर लाया गया था। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम से सोनी ने देहरादून और मसूरी में कई अवैध संपत्तियाँ बनाई हैं, जिनमें अधिकांश उसके रिश्तेदारों, परिचितों और दलालों के नाम पर हैं।

महिलाओं के जरिए चलता था करोड़ों का नेटवर्क, कई अफसर-राजनीतिक संपर्कों की भी जांच

एसआईटी ने शिमला बाईपास, घंटाघर, पलटन बाजार, डालनवाला, पीएनबी एनक्लेव और एफआरआई के पास मौजूद वीवीआईपी कॉलोनियों में सोनी के संपर्क में रहे कई लोगों की तलाश की, लेकिन कई फोन स्विच ऑफ मिले।

सूत्रों के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद देहरादून में बस चुके कुछ बड़े अधिकारियों के भी सोनी से गहरे संबंध रहे हैं, जिन्हें एसआईटी ट्रेस कर रही है। टीम ने एक दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी देने से बचता रहा। जांच के दौरान एसआईटी को टैगोर विला की एक महिला की तलाश है, जो सोनी के लिए नेटवर्क तैयार करती थी और ब्लू चिप कंपनी में निवेश करवाने का काम संभालती थी। निवेश की रकम पहले सोनी के खातों में पहुंचती थी, फिर वहाँ से उसके जरिए बिटकॉइन में बदली जाती थी। एसआईटी ने देहरादून के कई बैंकों से अकाउंट डिटेल जुटाई है और जिन स्थानों पर सोनी का मूवमेंट मिला, वहां की सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली जा रही है। जिन होटलों में वह ठहरा था, वहाँ से भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। देहरादून की जांच के बाद टीम रवींद्र नाथ सोनी को लेकर दिल्लीङ्कएनसीआर जाएगी, जहां उसके कई संपर्कों, होटलों और निवेशों की गहन जांच की योजना है एसआईटी को पता चला है कि हर राज्य में सोनी ने कॉर्पोरेट दफ्तरों की तरह टीम बना रखी थी, जिसमें महिलाओं को अहम जिम्मेदारियाँ दी गई थीं चाहे फाइनेंस हो या निवेश प्रबंधन। कई बैंक खातों के विवरण अभी भी नहीं मिल पाए हैं, जिसके लिए टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है। विदेशों से ईमेल के जरिए सोनी के खिलाफ आ रही शिकायतें स्थिति को और गंभीर बना रही हैं सूत्रों ने यह भी बताया कि सोनी बड़े होटलों में पार्टियां देकर लोगों को अपनी ब्लू चिप कंपनी में निवेश के लिए लुभाता था और महंगे गिफ्ट तक देता था। इतना ही नहीं, उसने देहरादून और मसूरी के कुछ राजनीतिक संबंधों और मीडिया जगत में भी गहरी पैठ बना रखी थी, जिसकी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।

नशे की लत पूरी करने के लिए बना लिया कट्टा सप्लायर गैंग

जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन के बाद खुफिया अलर्ट

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। रेलबाजार पुलिस ने अवैध असलहा कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से पांच कट्टे और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी कट्टे बेचकर नशे की लत को पूरा करते थे।थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि बुधवार देर रात प्राप्त सूचना के आधार पर शिवनारायण टंडन सेतु के नीचे रेलवे लाइन के पास छापेमारी की गई। यहां चार युवक संदिग्ध हालात में मिले। तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध असलहे और कारतूस बरामद हुए।पूछताछ में आरोपियों की पहचान अनवरगंज के कुली बाजार निवासी अल्तमस, बेकनगंज निवासी साहबान, बजरिया के कंघी मोहाल निवासी आजम उर्फ आशू और सरसैया घाट निवासी विशाल निषाद के रूप में हुई। आरोपियों ने कबूल किया कि वे दूसरे जिलों से कट्टे मंगवाते थे और उन्हें बेचकर कमाए पैसों से नशा करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इस महीने चौथी बार कानपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। दिसंबर के 11 दिनों में कानपुर चौथी बार गुरुवार को प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा है। इसके पहले चार, पांच और छह दिसंबर को शहर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा था। इसके साथ ही सीएसए के मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 23 साल बाद 11 दिसंबर को न्यूनतम तापमान सबसे कम छह डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके पहले वर्ष 2002 में 11 दिसंबर को न्यूनतम तापमान चार डिग्री रहा था।

मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को कानपुर प्रदेश में सबसे ठंडा और दूसरे नंबर पर इटावा और बरेली (7.2 डिग्री) रहे हैं। इसके पहले पांच और छह दिसंबर को कानपुर सबसे सर्द और इटावा दूसरे नंबर पर रहा। चार दिसंबर को कानपुर (5.7 डिग्री) के बाद बरेली (6.9 डिग्री) सबसे ठंडा रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान साफ रहने और माहौल में नमी बढ़ने के कारण रात का न्यूनतम पारा नीचे गिर जा रहा है।

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि ध्रुवीय हवाएं आने के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने से नमी बढ़ रही है। इस वजह से धुंध और कोहरा सुबह शाम बढ़ेगा। नमी बढ़ी तो धुंध की चादर मोटी होती चली जाएगी। अभी दृश्यता सामान्य 300 मीटर की तुलना में 50 मीटर तक होने का अनुमान है।

दिन चढ़ने के बाद धुंध और कोहरा छंट जाएगा। दिन में धूप नरम रहेगी। उन्होंने बताया कि 13-14 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान है। इसके आने से माहौल में नमी का प्रतिशत और बढ़ेगा। इससे धुंध भी बढ़ेगी। इसके अलावा राजस्थान में भी चक्रवाती हवाओं का घेरा बनेगा।

भारत में घुसपैठ पर सख्त एक्शन!

» बांग्लादेशी और रोहिंग्या नेटवर्क पर कसा शिकंजा, सरकार की कार्रवाई से बढ़ी सुरक्षा

» बायोमेट्रिक तकनीक ने बढ़ाई पहचान की रफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

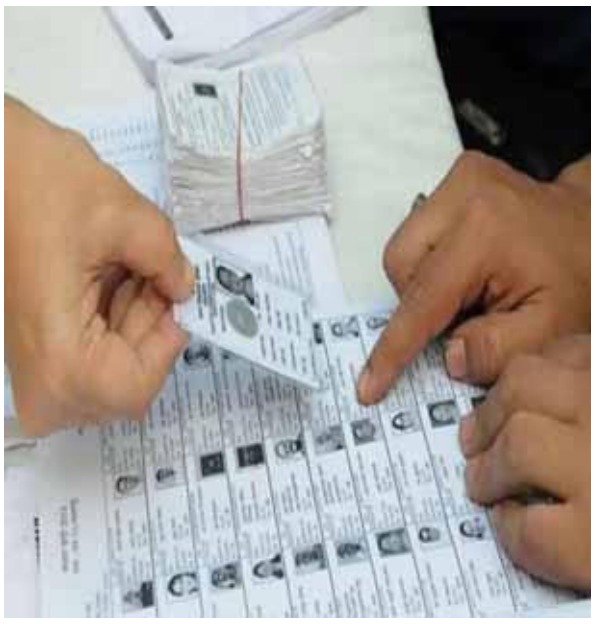

लखनऊ। भारत की सीमाओं से होने वाली अवैध घुसपैठ के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त मुहिम तेज हो गई है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के बढ़ते जाल पर अब मजबूत तकनीकी, कानूनी और प्रशासनिक शिकंजा कसता दिख रहा है। पहचान से लेकर निष्कासन तक की प्रक्रिया में तेजी आने के संकेत हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिल रही है। केंद्र सरकार ने आधार प्रणाली को और मजबूत करते हुए संदिग्ध दस्तावेजों की बायोमेट्रिक जांच शुरू की है। फिंगरप्रिंट और आईरिस मिलान के जरिए फर्जी आधार और पहचान पत्रों का खुलासा तेजी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इस तकनीक से कई नेटवर्कों का पर्दाफाश हुआ है।

घुसपैठ के खिलाफ सरकार की समन्वित कार्रवाई से देश के कई राज्यों में सुरक्षा ढांचा मजबूत हुआ है। बढ़ती निगरानी, तकनीकी जांच और तीव्र निष्कासन प्रक्रिया से स्पष्ट संकेत हैं कि भारत अब अवैध घुसपैठ पर निर्णायक नियंत्रण की ओर बढ़ रहा है।

बीएसएफ की कड़ी निगरानी,2600 से अधिक घुसपैठिए पकड़े गए

बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर 2024ङ्क2025 के दौरान 2601 घुसपैठियों को पकड़ा है। सख्त पेट्रोलिंग और ड्रोन मॉनिटरिंग के कारण सीमा पार करना अब पहले से कहीं कठिन हो गया है। कई संदिग्धों को मौके पर ही वापस खदेड़ा गया।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली समेत देश के 18 डिटेंशन सेंटरों में 1500 से ज्यादा विदेशी नागरिक रखे गए हैं।

2025 में मुंबई पुलिस ने 1001 बांग्लादेशियों को वापस भेजा, जबकि असम समेत कई राज्यों में 142 रोहिंग्याओं का निष्कासन किया गया। नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने से मामलों के निपटान में तेजी आई है।

उत्तर प्रदेश सरकार सबसे अधिक आक्रामक रोहिंग्या बस्तियों में बड़ी कार्रवाई

योगी सरकार ने घुसपैठ के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान छेड़ रखा है।

700ङ्क800 रोहिंग्या की पहचान पूरी,250 संदिग्धों का सत्यापन जारी,मेरठ में 500 क्षमता वाला बड़ा डिटेंशन सेंटर तैयार,हर मंडल में सेंटर निर्माण प्रक्रिया तेज,

सहारनपुर में 'ऑपरेशन टॉर्च' के तहत झुग्गियों, रेलवे स्टेशनों और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय तलाशी जारी है। लखनऊ में अभियान के बाद 160 घुसपैठिए रातों-रात इलाके से गायब हो गए—जो प्रशासनिक कार्रवाई के बढ़ते प्रभाव का संकेत है।

फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर हो रही कड़ी कार्रवाई

पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में फर्जी आधार और मतदाता पहचान पत्र बनाने वाले एजेंट नेटवर्क पर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है।

कई गिरोह सक्रिय रूप से पकड़े गए हैं, जिससे फर्जी पहचान पत्र बनना मुश्किल हो गया है। चुनौतियों के बीच उम्मीदें मजबूत

मानवाधिकार जांच, सीमित संसाधन और सीमा पार होने के कुछ घंटे बाद दोबारा लौट आने जैसी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की सख्ती से घुसपैठियों में खौफ साफ दिख रहा है।

सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि डिजिटल निगरानी, संयुक्त टीमें और तेज सत्यापन से आने वाले महीनों में और बड़ी सफलता मिलेगी।

51 लाख से भरी थाल लौटाई... बुलंदशहर में दूल्हे ने शगुन में लिया सिर्फ चांदी का सिक्का

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बुलंदशहर। बुलंदशहर में दूल्हे ने दहेज के 51 लाख रुपये लौटाए और चांदी का एक सिक्का लेकर विवाह किया। सर्व खाप द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में मथुरा की कृष्णा से बुलंदशहर के विवेक ने बगैर दहेज के विवाह किया।

दहेज प्रथा के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए बुलंदशहर के एक दूल्हे ने विवाह में मिले 51 लाख रुपये की नकदी को वापस लौटा दिया। इसके बजाय, उन्होंने चांदी के एक सिक्के के साथ अपनी वधू कृष्णा को स्वीकार किया।

यह दहेज मुक्त विवाह मुजफ्फरनगर के सोरम में आयोजित सर्व खाप पंचायत के निर्णयों के अनुरूप हुआ, जहां जाट समाज द्वारा बिना दहेज शादी करने और मृत्यु भोज का बहिष्कार करने की अपील की गई थी।

हाल ही में मुजफ्फरनगर के सोरम में आयोजित सर्व खाप पंचायत में, समाज के गणमान्य व्यक्तियों और खाप सरदारों ने सामूहिक रूप से दहेज प्रथा और मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने का आह्वान किया था। इस पंचायत का उद्देश्य समाज में समानता और सादगी को बढ़ावा देना था। पंचायत के इस निर्णय ने कई युवा जोड़ों को प्रेरित किया है, और बुलंदशहर में विवेक और कृष्णा का विवाह इसी प्रेरणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

विवेक का सराहनीय कदम

बुलंदशहर के विवेक, जो मथुरा की रहने वाली कृष्णा के साथ विवाह बंधन में बंध रहे थे, ने सर्व खाप द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करते हुए यह अनूठी पहल की। मेरठ रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में संपन्न हुए इस विवाह समारोह में, विवेक ने न केवल 51 लाख रुपये की नकदी को माथे से लगाकर वधु पक्ष को वापस लौटाया, बल्कि उन्होंने सादगी का प्रतीक के रूप में चांदी के एक सिक्के के साथ विवाह संपन्न किया।विवेक और कृष्णा के इस दहेज मुक्त विवाह की सर्व समाज ने खुलकर सराहना की है। यह कदम न केवल दूल्हे के साहसिक निर्णय को दर्शाता है।

रूरा: बालू खोदो, पेड़ काटो...बस पुलिस को समझते रहो!

» रात भर चलती जेसीबी, अनजान बनी रही पुलिस

» माफियाओं और अवैध कार्यो का गढ़ बनता जा रहा है रूरा और आसपास का क्षेत्र

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिंगाई में नहर और रजबहे की बालू खनन कर रहे माफिया

कानपुर देहात।जिला कानपुर देहात पहले से ही खनन और माफियागिरी को लेकर बदनाम है लेकिन इसमें सुधार भी नहीं दिख रहा है। जिसको जहां मौका मिलता है कार्यों को अंजाम दे देता है। जीरो टालरेंस नीति वाली योगी सरकार में माफियाओं के हौंसले बुलंद होना लाजिमी है। क्षेत्र में दिन रात बालू, मिटटी का खनन चल रहा है। यहां तक की हरे पेड तक काटकर बेंचे जा रहे हैं लेकिन सब जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं।

ताजा प्रकरण रूरा थाना क्षेत्र के ग्राम तिंगाई का सामने आया है। यहां पर नहर पुल के पास नहर और रजबहे की सफाई से बडी मात्रा में निकली बालू पर नजर खनन माफियाओं की लग गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गत गुरूवार रात 11 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक जेसीबी लगाकर आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर लगाकर बालू का खनन किया गया। ट्रैक्टर बालू भरकर मुख्य मार्गो से होते हुए निकलते रहे लेकिन पुलिस गश्त को पतातक नहीं चला।

कुछ ग्रामीणों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को रात में ही दी लेकिन इग्नोर कर दिया गया गया। इससे पता चल रहा है कि स्थानीय पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है।

सूत्रों का दावा है कि नगर पंचायत रूरा के एक सभासद बीजेपी के स्थानीय नेता के इशारे पर क्षेत्र में मिटटी, बालू का अवैध खनन करता है। इसमें पुलिस को भी हिस्सा जाता है।

क्षेत्र में कई जगह हरे पेडों की कटान की भी शिकायतें हुई लेकिन रूरा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

स्थानीय पुलिस मामलों के कागजी निस्तारण में लगी रहती है लेकिन जमीनी हकीकत बदतर है। मामले में थानाध्यक्ष अमित शुक्ला से बात करने के लिए प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं हो सकी। सीओ अकबरपुर संजय सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी करेंगे, वैसे एसडीएम साहब को बता दें वही देखेंगी।

एसडीएम अकबरपुर ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है, एक्शन लिया जाएगा।

एकमुश्त समाधान योजना के तहत कैम्प का लोगों ने लिया लाभ

» बिजली बिलों पर मूलधन पर छूट और ब्याज माफी पर अधिक से अधिक लोग उठाएं लाभ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा विकास खण्ड के सिहारी गांव में शुक्रवार को एकमुश्त समाधान योजना के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर राहत प्रदान करना था। उपभोक्ताओं ने इस दौरान अपने लंबित बिलों का भुगतान कर योजना का लाभ उठाया।शिविर में कई बकायादार उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा किए गए। उन्हें बिलों पर लगने वाले ब्याज में छूट का लाभ भी मिला, जिससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत हुई। कैंप में विद्युत विभाग के जेई अजय सिंह, बाबू दीपक सिंह, व विभाग के कर्मचारी लाइनमैन आनंद ,चमन, पहलाद , कल्लू भदौरिया, राजकुमार, अवधेश कुमार,सहित कई उपभोक्ताओं भी मौजूद रहे।

एसपी ने पुलिस लाइन में निरीक्षण कर ली परेड की सलामी

» पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी रजिस्टरों को चेक कर दिए कई निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले की पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण कर रिक्यूट आरक्षियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

शुक्रवार को जनपद की पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय द्वारा पुलिस लाइन में शुक्रवार की परेड में सम्मिलित होकर परेड का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्यूट आरक्षियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुशासन, समयबद्धता, शिक्षण विधि, फिजिकल ट्रेनिंग एवं व्यवहारिक ज्ञान को लेकर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा–निर्देश प्रदान किए गए।

निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में एकरूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई गई। वहीं इसके बाद पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्ड की सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

संत बनाम पुलिस, 'अराजक तत्वों' की साजिश या जमीन हड़पने का खेल?

रघुनाथ दास छावनी की गोशाला पर घमासान

» संतो का आरोप, निर्विवाद भूमि पर बिना किसी आदेश के पुलिस रोक लगा रही

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या की संत परंपरा और धार्मिक संस्थानों की प्रतिष्ठा के बीच एक नई आग भड़क उठी है और इस बार अखाड़े के बीच में है छावनी स्थित रघुनाथ दास की गोशाला, जिसकी बाउंड्री निर्माण को लेकर विवाद अब टकराव बन चुका है। शिष्य संत दास उर्फ राजेश सिंह मानव ने पुलिस चौकी रायगंज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ अराजक तत्वों के इशारे पर पुलिस जानबूझकर निर्माण कार्य में बाधा डाल रही है।

निर्विवाद भूमि पर बिना आदेश पुलिस रोक लगा रही है यह किसके दबाव में हो रहा है? संत दास के इस सवाल ने पूरे मामले को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। संत दास के अनुसार, गोशाला गाटा संख्या 358, 395 और 396 पर बनी हुई है, और जमीन पूरी तरह निर्विवाद है। लंबे समय से टूटी बाउंड्री के कारण छोटे बछड़े अक्सर बाहर निकल जाते हैं, जबकि बाहरी सांड अंदर घुसकर गोवंश को नुकसान पहुंचाते हैं। सुरक्षा के लिए बाउंड्री निर्माण जरूरी है, लेकिन कुछ लोग भूमि हथियाने की नीयत से पुलिस को

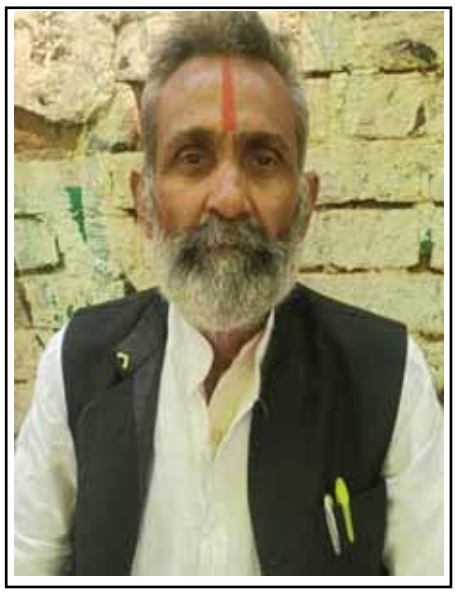

गुमराह कर रहे हैं, संत दास का यह आरोप अयोध्या के धार्मिक-सामाजिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर रहा है।सबसे बड़ा आरोप की पुलिस बिना किसी लिखित आदेश, बिना किसी दिशानिर्देश और बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के निर्माण कार्य रुकवाने पहुंच जाती है।संत दास ने तीखा सवाल दागा पुलिस किस कोड के तहत कार्य रोक रही है? किसके आदेश पर? यह स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा? स्थिति तब और गंभीर हुई जब उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन इसी तरह हस्तक्षेप करता रहा, तो वह कोतवाली के सामने शंख बजाकर अनशन करने को मजबूर होंगे। अयोध्या की संत परंपरा में यह भाषा असामान्य नहीं है। लेकिन इसे इस बार संत-संस्था बनाम पुलिस-प्रशासन के सीधे संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। धार्मिक भूमि विवादों की आग में अतीत में कई बार अयोध्या झुलस चुकी है, और यह प्रकरण भी जमीन, दबंगई, पुलिस रोल और धर्मस्थल की मर्यादा इन चारों को एक ही कहानी में उलझा रहा है। अब गेंद प्रशासन के पाले में है लिखित आदेश दिखाए या कार्रवाई पर रोक लगाए।

कौशलपुरी कॉलोनी में जल निकास की समस्या का जल्द होगा सुधार

» महापौर ने निरीक्षण कर क्षेत्र के लोगों को दिया आश्वासन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। 'नगर की सरकार आपके द्वार' अभियान के तहत महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने कौशलपुरी कॉलोनी व आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जलभराव की समस्या पर नाराजगी जताते हुए महापौर ने नाले की तत्काल सफाई, पंप लगाकर पानी निकासी और स्थायी समाधान तैयार करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान निराला नगर की समोसा गली, हनुमान मंदिर क्षेत्र, खोजनपुर और विष्णुपुरी कॉलोनी में टूटी नालियों, प्रकाश व्यवस्था और लटके बिजली के तारों की शिकायतें मिलीं। महापौर ने नाली निर्माण, पटिया डालने, नई स्ट्रीट लाइट लगाने, पोल स्थापित कर तार ऊंचे करने तथा पार्क में ओपन जिम लगाने के आदेश दिए। निरीक्षण में पार्षद, अधिकारी और नगर निगम टीम मौजूद रही।

जनहित में लग रहीं पानी की टंकी का पड़ोसी ने किया विरोध

एमएलसी बोले, क्षेत्रीय लोग आपस में विवाद कर रहे हैं समझौता कर ले टंकी लग जाएगी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नगर के हरबंश मोहाल थाना क्षेत्र स्थितदानाखोरी में क्षेत्रीय जनता की सुविधा के लिए लगाई जा रही पानी की टंकी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय निवासी रामजी द्विवेदी द्वारा अपनी निजी भूमि (चबूतरे) पर सरकारी टंकी लगवाने की सहमति देने के बावजूद पड़ोसी द्वारा आपत्ति जताई जा रही है।

रामजी द्विवेदी ने इस संबंध में हरबंश मोहाल थाने में प्रार्थना पत्र देकर पड़ोसी प्रदीप कुमार अवस्थी पर जनहित व सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की बड़ी आबादी स्वच्छ पेयजल के लिए लंबे समय से परेशान है। लोगों की इस समस्या को देखते हुए एमएलसी सलिल विश्नोई ने अपनी विधायक निधि से पानी की टंकी स्वीकृत कराई है। शिकायतकर्ता के अनुसार जब टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो पड़ोसी द्वारा बेवजह विरोध कर कार्य रुकवा दिया गया। जबकि टंकी लगाने का स्थान उनकी निजी भूमि है और अनुमति भी उन्हीं की ओर से दी गई है। रामजी द्विवेदी का कहना है कि यह परियोजना पूरी तरह जनहित में है और इसके रुकने से सैकड़ों लोग साफ पानी से वंचित रह जाएंगे। इस मामले में एमएलसी सलिल विश्रोई का कहना है कि हमारी तरफ़ से तो टंकी लग रहीं क्षेत्रीय लोग आपस में विवाद कर रहे हैं समझौता कर ले टंकी लग जाएगी।

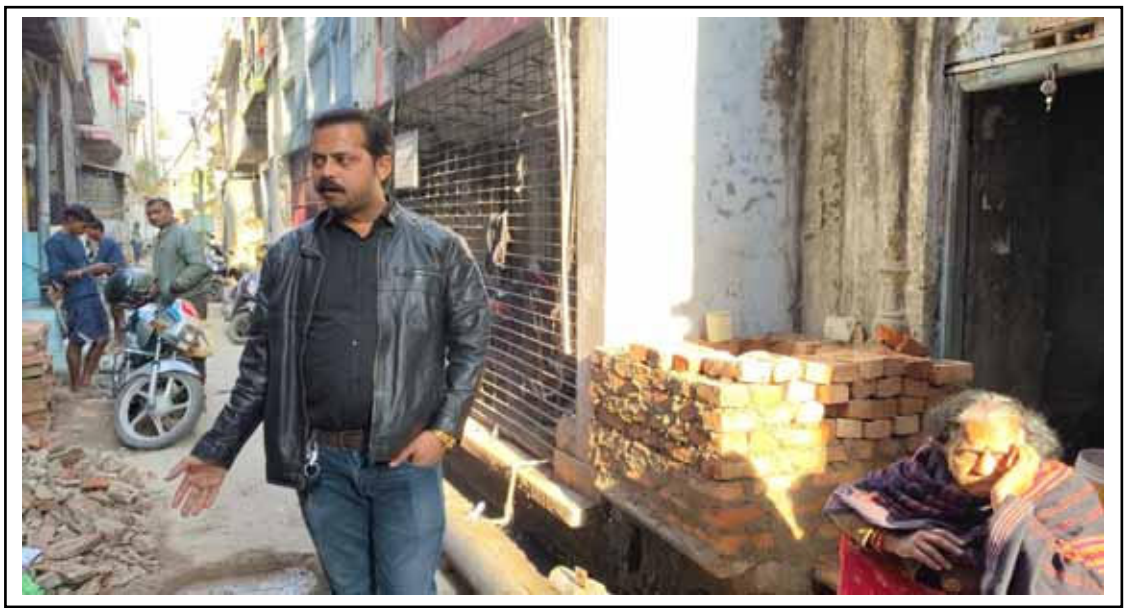

गोरखपुर में फर्जी 'आईएएस' का हुआ बड़ा पर्दाफाश

तीन राज्यों में फैला जालसाजी का नेटवर्क, करोड़ों की ठगी उजागर

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गोरखपुर। पुलिस ने अपने आप को उच्च प्रशासनिक अधिकारी बताकर वर्षों से लोगों को ठगने वाले गौरव कुमार सिंह उर्फ़ ललित किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हर महीने लगभग पाँच लाख रुपए सिर्फ़ तथाकथित 'अधिकारी प्रोटोकॉल' बनाए रखने पर खर्च करता था। सफ़ेद इनोवा में लालङ्कनीली बत्ती, आगे-पीछे 10 से 15 लोगों की टीम और गाँवों में औचक दौरे–इन्हीं दिखावों के दम पर वह लोगों को भ्रमित करता रहा।

जाँच में सामने आया कि बिहार के भागलपुर में एक दौरे के दौरान उसकी मुलाक़ात असली उपजिलाधिकारी से हो गई। रैंक और बैच को लेकर पूछताछ पर आरोपी ने उपजिलाधिकारी से बदसलूकी तक की, लेकिन अधिकारी ने कार्रवाई से परहेज़ किया।

पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल जब्त किए हैं, जिनमें उसकी चार प्रेमिकाओं की बातें मिली हैं। तीन महिलाएँ गर्भवती बताई जा रही हैं और सभी उसे वास्तविक अधिकारी समझती थीं। आरोपी ने बिहार की एक युवती से विवाह भी कर रखा था।

गौरव कुमार सिंह अपने साले अभिषेक कुमार की सहायता से समाज माध्यम पर स्वयं को उच्च अधिकारी के रूप में प्रचारित करता था।

जालसाजी के विस्तार के लिए उसने गोरखपुर निवासी परमानन्द गुप्ता को भी साथ मिला लिया। बीते तीन वर्षों में इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड तक अपना नेटवर्क फैला लिया था।बड़ी कंपनियों, ठेकेदारों और कारोबारियों को सरकारी काम दिलाने का प्रलोभन देकर वह कृत्रिम बुद्धि से तैयार कथित निविदाएँ दिखाता था। बिहार के एक कारोबारी से उसने चार सौ पचास करोड़ के ठेके का झाँसा देकर पाँच करोड़ रुपए और दो इनोवा गाड़ियाँ तक ऐंठ ली थीं।

पुलिस अब पूरे नेटवर्क, लेन–देन और सहयोगियों की भूमिका की गहन जाँच कर रही है। प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग कर लोगों से अरबों के सपने दिखाकर ठगी करने वाला यह बड़ा प्रकरण पुलिस की सजगता से उजागर हुआ है।

एक पत्नी और चार प्रेमिकाएं, तीन गर्भवती

जांच में सामने आया है कि आरोपी की निजी जिंदगी भी उतनी ही चौंकाने वाली है। उसकी एक पत्नी व चार प्रेमिकाएं हैं। जिसमें तीन गोरखपुर और एक सीतामढ़ी की रहने वाली है। जिनमें तीन गर्भवती पाई गई हैं। आरोपी जालसाज इन सभी पर वह महंगे मोबाइल, ज्वैलरी और लाखों रुपये खर्च करता था। महंगे कपड़े और ब्रांडेड चीजों का शौकीन आरोपी अपने आपको हाई प्रोफाइल अधिकारी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता था।

औरैया में 314 ने लिए सात फेरे, तीन ने कहा कुबूल है

»मुयमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 317 जोड़े एक-दूसरे के हुए

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

औरैया। औरैया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ककोर स्थित तिरंगा मैदान में 317 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इनमें से 314 जोड़ों ने हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया, जबकि 3 जोड़ों का निकाह पढ़ाकर उन्हें जीवनसाथी बनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्यमंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. सर्वेश कठेरिया ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी धूमधाम से कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कमी महसूस न हो। सदर विधायक गुडिया कठेरिया ने नवविवाहित जोड़ों को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवनसाथी का चुनाव कर सुखमय भविष्य की राह चुनी है। जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे ने इस आयोजन को सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोगों को एक साथ विवाह बंधन में बांधता है। दिबियापुर के पूर्व विधायक लाखन सिंह राजपूत ने इस दिन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में गरीब बेटियों की शादी धूमधाम से की जा रही है। उन्होंने सनातन धर्म में पाणिग्रहण संस्कार को सर्वोत्तम बताया और कहा कि दांपत्य जीवन में पति–पत्नी एक–दूसरे के पूरक होते हैं।अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की सदस्या ने भी नवविवाहितों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती, मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अविनाश चंद्र मौर्य, अपर जिलाधिकारी न्यायिक नीरज प्रसाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी सतीश कुमार पांडेय, परियोजना निदेशक डीआरडीए मनीष कुमार मौर्य, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अनूप गुप्ता, नगर पंचायत दिबियापुर अध्यक्ष राघव मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख अजीतमल रजनीश पांडेय सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक और नवविवाहित जोड़ों के अभिभावक उपस्थित रहे।

दो नेताओं की तकरार में पूरी कमेटी का कत्ल!

अयोध्या में सपा की 'सियासी सर्जरी'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।अयोध्या की सियासत इन दिनों रिश्तों, रसूख और रंजिशों के बीच चल रहे 'पार्टी ऑपरेशन' का अखाड़ा बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने जिले की जिला कमेटी के साथ ही महानगर कमेटी को भी एक झटके में भंग कर दिया। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कहीं ज्यादा धारदार, ज्यादा तड़पती और ज्यादा राजनीतिक है। सूत्र बताते हैं कि यह कार्रवाई किसी संगठनात्मक सुधार का हिस्सा नहीं, बल्कि दो कद्दावर नेताओं की आपसी नाराजगी की चिंगारी है, जिसने पूरी कमेटी को धू-धू कर जला दिया।

» गोसाईंगंज विधानसभा के प्रभारी की शिकायत सीधे पार्टी मुखिया के दरबार में पहुंची

सबसे बड़ा विस्फोट गोसाईंगंज विधानसभा से हुआ, जहां प्रभारी बनाए गए लौटनराम निषाद लगातार पार्टी नेतृत्व को शिकायत भेज रहे थे कि जिला कमेटी उनकी कोई दरकार नहीं कर रही, न बैकअप, न सहयोग, न रणनीति। और यह शिकायत सीधे पार्टी मुखिया के दरबार में पहुंची।

सपा के दिग्गज सांसद अवधेश प्रसाद के साथ माथापच्ची के बाद फैसला हुआ—जिला कमेटी खत्म, और इसका छाया प्रभाव महानगर कमेटी पर भी पड़ा, जो अब बस नाम मात्र रह गई। लेकिन असली आग यहां से शुरू होती है।

जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव अयोध्या में खुद को यादव राजनीति का केंद्रीय मोहरा बनाना चाहते

थे। मगर पार्टी के बड़े नेताओं की पहली पसंद हमेशा रही है आनंदसेन यादव, पूर्व सांसद मित्रसेन के पुत्र और पूर्व मंत्री, जिनकी पकड़ संगठन और बिरादरी दोनों में मजबूत है।

सूत्र बताते हैं कि पारसनाथ यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे प्रभावशाली यादव चेहरा बनकर टिकट की दौड़ में उतरने की तैयारी में थे। लेकिन लौटनराम निषाद का असंतोष और उस असंतोष का लखनऊ तक पहुंचना उनकी पूरी

रणनीति को ध्वस्त कर गया। नतीजा—जो लड़ाई दो नेताओं के बीच शुरू हुई थी, उसमें पूरी कमेटी मारी गई, और सपा की अयोध्या इकाई इस वक्त अपनी ही राजनीति के 'पोस्टमार्टम टेबल' पर पड़ी है। अयोध्या में यह फैसला केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, आने वाले चुनावी समर से पहले सपा की अंदरूनी जंग का पहला प्रहार माना जा रहा है। अब अगला कदम कौन, किस पर और कब चलाता है यही देखना बाकी है।

अयोध्या के पर्यटन नक्शे पर कोरिया की रानी हो पार्क एक नई चमक

कोरियन विलेज, टेंपल और अस्थायी प्रोजेक्ट अब मिली हरी झंडी

मेगा प्रोजेक्ट की हरी झंडी और डेढ़ साल की देरी पर उठ रहे सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। सरयू तट पर बना कोरिया की रानी हो पार्क अयोध्या के पर्यटन नक्शे पर एक नई चमक बनकर उभरने जा रहा है। 24 दिसंबर से इसे पूरी तरह विकसित रूप में पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, लेकिन इस चमकदार उद्घाटन के पीछे की कहानी उस डेढ़ साल लंबी प्रशासनिक देरी, फाइलों में अटके अनुमोदन और पावर सप्लाई की जटिल लड़ाई को भी उजागर करती है, जिसने पूरे प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब जब पार्क फिर से सांस ले रहा है, सवाल यह भी उठ रहा है क्या रानी हो पार्क को शुरुआत से ही वह राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन नहीं मिला, जिसकी जरूरत थी?

वेंडर कंपनी इंडियन सैनिटेशन वार्ड बॉय एंड हॉर्टिकल्चर के एमडी राहुल शर्मा कहते हैं कि पर्यटन विभाग ने पार्क बनाया जरूर था, मगर कंपनी को अस्थायी निर्माण कोरियन विलेज, कोरियन मंदिर, डुप्लेक्स कॉटेज,कोरियन फूड और अवध व्यंजनों का रेस्टोरेंट, गेम जोन, रिसेप्शन, कैफेटेरिया के लिए अनुमति ढाई साल बाद मिली। यह देरी ही पार्क के 'सुनसान' दिनों की सबसे बड़ी वजह रही। लेकिन अब मंडलीय आयुक्त राजेश कुमार और मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के हस्तक्षेप के बाद पावर सहित सभी अवरोध हट गए हैं।कोरियन विलेज लगभग 1000 वर्ग फुट में तैयार होगा जिसमें 6 कोरियन हट,2 प्रेयर हॉल एक कोरियन टेंपल,अस्थायी रूप से बनाए जाएंगे। चीफ कोऑर्डिनेटर वंदना शर्मा बताती हैं कि आश्चर्यजनक रूप से अब तक पार्क में रानी हो की प्रतिमा तक नहीं थी। अब कोरिया सरकार से 10 फुट ऊँची रानी हो की प्रतिमा कोरियाई देवताओं और महापुरुषों की मूर्तिया अयोध्या पहुंच चुकी हैं। इन्हें पार्क में उपयुक्त स्थलों पर स्थापित किया जाएगा। कोरिया की विशेषज्ञ टीम भी निरीक्षण के लिए आ सकती है जो इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान देगी।

इंडो-कोरियन मेला, अयोध्या में नया सांस्कृतिक संगम

24 से 26 दिसंबर 2025 तक इंडो-कोरियन क्रिसमस मेला आयोजित होगा। इसमें लाइव सांस्कृतिक कार्यक्रम, तुलसी पर्व कोरियन फूड स्टॉल, खेल प्रतियोगिताएं,कोरियाई वस्त्रों की बिक्री,जैसे आयोजन विदेशी और भारतीय पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बनेंगे। पर्यटन विभाग ने 18 करोड़ की लागत से 10,000 वर्ग फुट में पार्क बनाया था। 2023 में विभाग, अयोध्या संरक्षण समिति और वेंडर कंपनी के बीच अनुबंध भी हो गया था। 4 मार्च 2024 को सीएम ने इसका लोकार्पण भी कर दिया। लेकिन अस्थायी निर्माण की अनुमति नहीं,बिजली आपूर्ति में अवरोध,प्रशासनिक हस्तक्षेप,स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव,इन सबने प्रोजेक्ट को फ्रीज़ कर दिया।अब जब हरी झंडी मिल गई है, पार्क तेज़ी से विकसित हो रहा है।

अयोध्या-कोरिया संबंधों का जीवंत स्मृति स्थल

अयोध्या–कोरिया रिश्तों का प्रतीक 2000 साल पुरानी कहानी यह पार्क महज एक पर्यटन स्थल नहीं यह 2,000 साल पुराने अयोध्या–कोरिया संबंधों का जीवंत स्मृति स्थल है। राजकुमारी सूरी रत्ना (रानी हो) अयोध्या से समुद्री मार्ग से दक्षिण कोरिया पहुंचीं, जहाँ उन्होंने राजा किम सुरो से विवाह किया और वहाँ की रानी बनीं। आज भी उनके वंशज हर वर्ष अयोध्या आकर सरयू तट पर श्रद्धांजलि देते हैं। एक ओर यह पार्क अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की छलांग देने वाला प्रोजेक्ट है, दूसरी ओर इसकी देरी प्रशासनिक उदासीनता और प्रक्रियागत ढिलाई की कड़वी कहानी भी कहती है।अब जब निर्माण तेज़ी से हो रहा है,

सवाल यह है क्या रानी हो पार्क अब राजनीतिक–प्रशासनिक दोराहे से निकलकर अयोध्या का ग्लोबल लैंडमार्क बन पाएगा।समय इसका जवाब देगा, लेकिन अभी के लिए सरयू तट पर कोरिया की यह सांस्कृतिक छाप नए दौर की शुरुआत करती दिख रही है।

झांसी में एसपी बोलीं- आरोपी घर पर नहीं मिला, नोटिस चस्पा किया गया

पूर्व विधायक दीपनारायण की 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी कुर्क

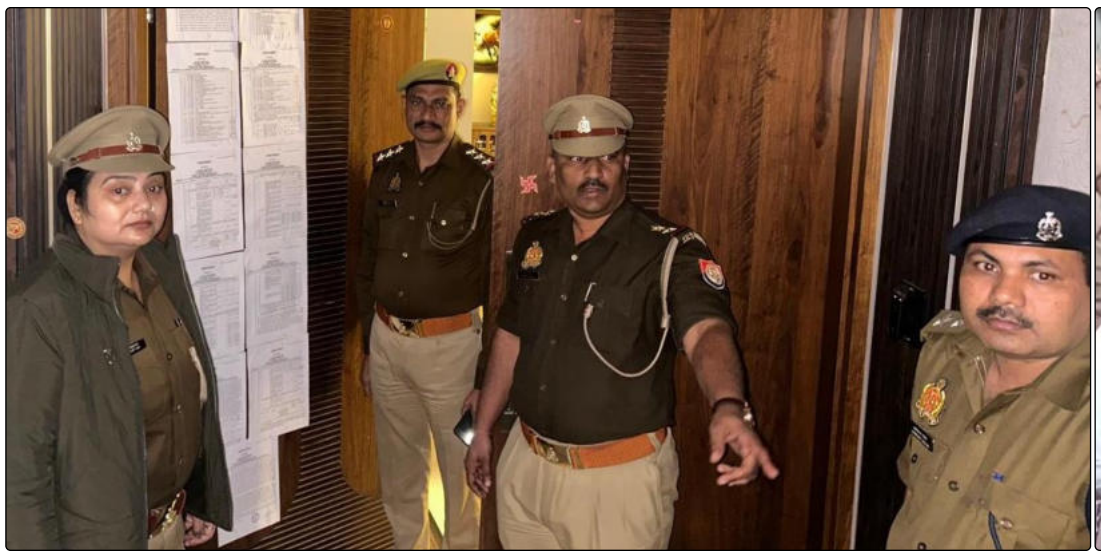

मारपीट-डकैती का मामला

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

झांसी। सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ न्यायालय जिलाधिकारी के आदेश पर करीब सवा 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के आदेश पर बृहस्पतिवार को एसपी सिटी के निर्देशन में सीओ सिटी व नवाबाद थाना प्रभारी की टीम ने मून सिटी पहुंचकर कुर्की नोटिस चस्पा किया। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक के निवास पर दो गवाहों के समक्ष कुर्की नोटिस चस्पा किया गया है।

मोंठ कोतवाली में पिछले दिनों दर्ज हुए मारपीट व डकैती प्रकरण में लापता चल रहे पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों में न्यायालय जिलाधिकारी ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने दीपनारायण यादव पुत्र बलभद्र निवासी गांव बूढ़ावली थाना मोंठ के विरुद्ध अवैध एवं अनियमित ढंग से अर्जित की गई 20 करोड़ 26 लाख 52 हजार रुपये की चल/अचल संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। एसएसपी के आदेश पर सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम व थाना प्रभारी नवाबाद जेपी पाल ने फोर्स के साथ आदेश की तामील कराने के लिए वांछित अभियुक्त की अनुपस्थिति में मून सिटी अपार्टमेंट, 11वीं मंजिल पर गवाहों की मौजूदगी में आदेश की प्रति चस्पा कर दी है। एसएसपी के आदेश पर सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम व थाना प्रभारी नवाबाद जेपी पाल ने फोर्स के साथ आदेश की तामील कराने के लिए वांछित अभियुक्त की अनुपस्थिति में मून सिटी अपार्टमेंट, 11वीं मंजिल पर गवाहों की मौजूदगी में आदेश की प्रति चस्पा कर दी है।

यूपी को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब बनाने की तैयारी

लखनऊ, स्वराज इंडिया ब्यूरो। आने वाले वर्षों में यूपी को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब बनाने की तैयारी है। इसको लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और राज्य मंत्री वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अरुण कुमार सक्सेना ने लखनऊ में बड़ी बैठक की। बैठक में प्रदेश के चारों टाइगर रिजर्व, 10 रामसर साइट्स सहित कई वेटलैंड के एकीकृत विकास के निर्देश दिए गए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन का भविष्य तेजी से नए आयाम गढ़ रहा है, इसी बदलते परिदृश्य में समग्र पर्यटन विकास, रिस्पांसिबल टूरिज्म और वन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग की भूमिका निर्णायक होगी।

राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा उत्तर प्रदेश के समृद्ध वन्य जीवन और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रस्तुत करना हमारा मूल उद्देश्य है। इको टूरिज्म न केवल स्थानीय समुदायों को रोजगार से जो?ता है, बल्कि प्रकृति संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी भी मजबूत करता है। टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स और राज्य के प्रमुख वेटलैंड्स में चल रहे विकास कार्यों से प्रदेश को 'वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब' बनाने की दिशा में नई ऊर्जा मिली है।

देश के कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत: योगी

बाराबंकी में मुख्यमंत्री ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास देश की कुल कृषि भूमि का 11 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन यूपी देश के कुल कृषि उत्पादन में 21 फीसदी योगदान देता है। यह बताता है कि प्रदेश का किसान मेहनती भी है और नवाचार की क्षमताओं से भी भरपूर है। सरकार प्रदेश के 28 जिलों में 4000 करोड़ की लागत से खेती में सुधार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है।

सीएम योगी शुक्रवार को हरख ब्लॉक के दौलतपुर गांव में पद्मश्री और प्रगतिशील किसान रामसरन वर्मा के फार्म पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तमाम योजनाएं चलाई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ने बड़े स्तर पर किसानों को राहत दी है।

सीएम योगी ने कहा कि परंपरागत खेती के साथ-साथ यदि किसान उच्च मूल्य वाली फसलों, सब्जियों, फल उत्पादन और प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ें तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने पद्मश्री रामसरन वर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों और नवाचार को अपनाने से सीमित भूमि पर भी शानदार उत्पादन संभव है। सरकार किसानों को इसी दिशा में प्रोत्साहित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी प्रगति के बिना समृद्ध भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार हर जिले में किसान प्रशिक्षण, मॉडल फार्म और आधुनिक मार्केट से जोड़ने की व्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खेती को लाभकारी बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।